नईदुनिया

उज्जैन को मूर्ति-शिल्प का केन्द्र बनाने के प्रयास किए जाएंगे: डॉ.यादव

■ विक्रम व्यापार मेले का आयोजन प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ■ मुख्यमंत्री ने की विक्रमोत्सव-2025 और विक्रम व्यापार मेले के आयोजन की समीक्षा

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन में स्मार्ट सिटी कार्यालय के सभा कक्ष में आगामी विक्रमोत्सव-2025 और विक्रम व्यापार मेले के आयोजन की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में विक्रम व्यापार मेले का आयोजन एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

सम्राट विक्रमादित्य न्याय, दानशीलता, सुशासन, वीरता की अद्वितीय मिसाल है। वे एक महान शासक थे। उन्होंने न केवल विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित कर देश से बाहर किया बल्कि सुशासन के सभी क्षेत्रों में उनका विशेष स्थान रहा है। सम्राट विक्रमादित्य के साहस, पराक्रम और पुरूषार्थ, उनकी कथाएं, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया विक्रम संवत्, उनके महान इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि उज्जैन को मूर्तिशील्प का केन्द्र बनाए जाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये। प्रदेश सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के विभिन्न आयामों को देश और विदेश के सामने लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ किया है। सम्राट विक्रमादित्य के विक्रम संवत् के प्रवर्तन के अवसर पर उज्जैन में आने वाले दिनों में भव्य आयोजन किया जाएगा। विक्रमादित्य की न्याय परंपरा पर विश्वविद्यालय में सेमीनार का आयोजन किया जाएगा। विक्रम व्यापार मेले में सरकार द्वारा निवेशकों को मंच प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं इन्हें और अधिक विकसित किया जाएगा। उज्जैन में धार्मिक पर्यटकों की संख्या में अत्यंत वृद्धि हुई है।

डॉ. यादव ने विक्रम व्यापार मेले के आयोजन और विक्रमोत्सव के आयोजन की समीक्षा की। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन से गत वर्ष आयोजित विक्रम व्यापार मेले के बारे में मूलभूत जानकारी दी। बताया गया कि इस वर्ष विक्रम व्यापार मेले के आयोजन के लिए शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर का चयन किया जाना प्रस्तावित है। बैठक में विक्रम व्यापार मेले-2025 के लिये स्थल के प्रस्तावित ले-आउट, प्रस्तावित दुकानों की जानकारी और आयोजन के संबंध में अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के व्यापार मेले में ऑटो एक्स-पो और धार्मिक पर्यटन को भी विशेष बढ़ावा दिया जाएगा।

बैठक में सांसद बालयोगी उमेशनाथ, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेडा, सतीश मालवीय, जितेन्द्र पण्ड्या, एडीजी उमेश जोगा, संभागायुक्त संजय गुप्ता, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जयति सिंह, विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक डॉ. श्रीराम तिवारी, डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुँवर, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रो. अर्पण भारद्वाज, नगर निगमायुक्त आशीष पाठक, बहादुर सिंह बोरमुण्डला, एमपीआईडीसी के राजेश राठौर, विशाल राजोरिया मौजूद थे।

सांस्कृतिक वैविध्य ही हमारी पहचान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि भारत विभिन्न धर्मों, समाजों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। सब मिलकर यहां सद्भावपूर्वक रहते हैं। सांस्कृतिक वैविध्य ही हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारी आस्था और जीवन मूल्य हमें विकास की ओर ले जाते हैं। योग, तप, साधना और साहचर्य से जीवन का समग्र विकास की शिक्षा सिर्फ भारतीय संस्कृति ही सिखाती है। समाज में जनजागृति लाने में महर्षियों की बड़ी अहम भूमिका रही है। महर्षि बालीनाथ बैरवा उन्हीं में से एक थे। वे परम संत थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को उज्जैन में महर्षि बालीनाथ बैरवा जयंती कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉ. यादव ने कहा कि जो असंभव दिखता है, वो केवल सनातन धर्म में ही संभव है। महर्षि बालीनाथ जी ने समाज की कुरीतियों, रूढ़ियों और बुराइयों को खत्म किया और सबको सद्मार्ग की ओर ले जाने का काम किया। उन्होंने बालीनाथ जी की स्मृति में देश के दूरदराज से आए बैरवा समाजजन का अभिनंदन करते हुए कहा कि इस प्रदेश स्तरीय सामाजिक कार्यक्रम में आकर वे बेहद प्रसन्न है। मुख्यमंत्री ने श्री अखिल जूनवाल द्वारा लिखित पुस्तक भीम वंदना का विमोचन भी किया। इसके बाद बैरवा समाज की बाईक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में राज्यमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार विभाग एवं उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, अखिल भारतीय बैरवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जारवाल, लालाराम बैरवा, राधेश्याम बैरवा, मुकेश टेटवाल, सीएल बैरवा, प्रभुराम उपस्थित थे।

अगले साल होगी राज्यस्तरीय पंचायत

डॉ. यादव ने कहा कि सरकार अगले साल बैरवा समाज की राज्य स्तरीय पंचायत का आयोजन करेगी। इसमें देश के विभिन्न अंचलों में रह रहे बैरवा समाजजनों को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हो रहे औद्योगिक विकास में बैरवा समाज के उद्योगपति और व्यवसायियों को जोड़कर बैरवा समाज का सर्वांगीण विकास करेगी। उन्होंने कहा कि बैरवा समाज के बच्चे खूब पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें, इसके लिए सरकार हर जरूरी प्रयास और सहयोग भी करेगी।

भोपाल से पीथमपुर तक बनेगा ग्रीन कॉरिडोर

पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ 12 कंटनरों से किया जाएगा अपशिष्ट का परिवहन

भोपाल(काप्र)।

संचालक गैस राहत एवं पुनर्वास स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की ओवर साइट कमेटी के निर्देशों एवं सुपरविजन अनुसार यूनियन कार्बाइड के शेष बचे 337 मीट्रिक टन रासायनिक अपशिष्ट के विनष्टीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

उन्होंने बताया कि 337 मीट्रिक टन यूसीआईएल अपशिष्ट की पैकिंग, लोडिंग और परिवहन सीपीसीबी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ विशेष 12 कंटेनरों से किया जायेगा। कंटेनर्स के साथ पुलिस सुरक्षा बल, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड तथा क्रिक रिस्पॉंस टीम रहेगी। यह कंटेनर लीक प्रूफ एवं फायर रेजिस्टेंट हैं। प्रति कंटेनर 2 प्रशिक्षित ड्राइवर नियुक्त किये गये हैं। इन कंटेनरों का मूवमेंट जीपीएस द्वारा मॉनिटर किया जायेगा। अपशिष्ट का परिवहन भोपाल से पीथमपुर टीएसडीएफ तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर शीघ्र किया जायेगा। श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में निकलने वाले रासायनिक तथा अन्य अपशिष्ट के निष्पादन के लिये धार जिले के पीथमपुर में एकमात्र प्लांट है, जहां पर भस्मीकरण से अपशिष्ट पदार्थों का विनष्टीकरण किया जाता है। यह प्लांट प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों द्वारा जनित खतरनाक एवं रासायनिक अपशिष्ट के सुरक्षित निष्पादन के लिये स्थापित किया गया है। यह प्लांट सेन्ट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशा-निर्देशानुसार संचालित है। सीपीसीबी की मॉनिटरिंग में सभी निर्धारित पैरामीटर अनुसार सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए 10 मीट्रिक टन अपशिष्ट विनिष्टिकरण का ट्रॉयल रन-2015 में किया गया। शेष बचे 337 मीट्रिक टन रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुक्रम में तथा उच्च न्यायालय द्वारा गठित ओवर साइट कमेटी/टास्क फोर्स कमेटी के निर्णय 19 जून 2023 के अनुक्रम में किया जा रहा है।

पीथमपुर में स्थापित कॉमन हैज़र्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज और डिस्पोज़ल फैसिलिटी अत्याधुनिक सुविधा है, जिसमें ख़तरनाक कचरे को सटीकता और सुरक्षा के साथ निष्पादन करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। री-सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड की सहायक कंपनी पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मेनेजमेंट प्रा.लि. द्वारा संचालित, यह सुविधा भस्मीकरण, लैंडफ़िल प्रबंधन और उत्सर्जन नियंत्रण के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग कर अपशिष्टों का निष्पादन करती है। अपशिष्टों के निष्पादन के दौरान इस सुविधा द्वारा लगातार जल एवं वायु मापन कार्य किया जाता है। यह सुविधा खतरनाक कचरे को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रूप से निपटाने और प्राकृतिक संसाधनों को दूषित करने के जोखिम को कम करने के लिये विशिष्ट समाधान प्रदान करती है। श्री सिंह ने बताया कि यूसीआईएल अपशिष्ट के विनिष्टिकरण के लिये केन्द्र सरकार स्तर पर ओवर साइट कमेटी का गठन जुलाई 2010 में केन्द्रीय मंत्री पर्यावरण एवं वन क्लाइमेंट चेंजेस की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें राज्य शासन के पर्यावरण मंत्री एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री सम्मिलित हैं। इसमें पर्यावरण एक्सपर्ट तथा भारत सरकार कॉउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत संचालित संस्थाएं नेशनल इन्वायरमेंटल एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट (एनईईआरआई) नागपुर, एनजीआरआई (नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट), हैदराबाद, सीपीसीबी (केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड), आईआईसीटी (इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी), हैदराबाद तथा एमपीपी सीबी के विशेषज्ञों के साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मिलित हैं। उक्त समिति को उच्च न्यायालय द्वारा ओवर साइट कमेटी/टास्क फोर्स के रूप में नामांकित किया गया है। कमेटी के निर्देशों एवं सुपरविजन के अनुसार विनिष्टिकरण का कार्य किया जा रहा है।

बोर्ड परीक्षा से पहले जान सकेंगे प्रश्न पत्रों का पैटर्न

पोर्टल पर अपलोड किए प्रादर्श प्रश्नपत्र, प्रैक्टिस में मिलेगी मदद

भोपाल(काप्र)।

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा फरवरी 2025 के आखिरी सप्ताह में शुरू होने वाली हैं। परीक्षाओं को देखते हुए दोनों ही कक्षाओं के छात्र तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही छात्रों के मन में जिज्ञासा रहती है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र कैसा आएगा और किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।

छात्रों की इस जिज्ञासा को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने पोर्टल पर दोनों ही कक्षाओं के प्रश्न पत्रों के मॉडल पेपर अपलोड किए हैं। इन्हें देखकर छात्र अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा और उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। बोर्ड ने प्रश्न पत्र अपलोड करने के साथ ही सर्कुलर भी जारी किया है और स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि पोर्टल पर जो प्रश्न पत्र अपलोड किए गए हैं, वे केवल प्रादर्श प्रश्न पत्र हैं। प्रश्न पत्र इसी तरह का आएगा और इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इन प्रश्न पत्रों में से कोई सवाल आएगा। इसके बारे कुछ कहा नहीं जा सकता। छात्र इन प्रश्न पत्रों को अपने अभ्यास के रूप में ले सकते हैं। परीक्षा से पहले इनके सवालों को भी तैयार कर सकते हैं।

निर्देश उसी तरह के रहेंगे, जैसे प्रादर्श प्रश्नपत्रों के: पोर्टल पर अपलोड किए गए 10वीं व 12वीं के प्रादर्श प्रश्नपत्रों में जिस तरह के निर्देश शुरुआत में दिए गए हैं, उसी तरह के निर्देश आगामी परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्रों पर भी देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए प्रश्नपत्र में किस नंबर से किस नंबर तक कितने अंक होंगे। उनकी शब्द सीमा कितनी होगी और किन किन प्रश्नों में विकल्प हैं। ऐसे में इन प्रश्नपत्रों से छात्रों को परीक्षा में आने वाले पेपरों के स्वरूप का पता चल जाएगा।

मेधावी छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं भी अपलोड: बोर्ड ने पोर्टल पर हर साल मेरिट में आने वाले मेधावी छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को भी अपलोड किया है। इन्हें देखकर छात्र अपनी परीक्षा में किस तरीके से उत्तर लिखना है, सीख सकते हैं, जिससे उनके भी नंबर भी परीक्षा में अधिक आएं।

नववर्ष का आगमन नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का अवसर: पटेल

भोपाल(काप्र)।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मंगलकामना की है कि नव वर्ष 2025 सभी के लिए सुख, शांति, सद्भाव, समृद्धि और सफलता लेकर आये। उन्होंने कहा है कि नव वर्ष का आगमन जीवन में नए संकल्प और लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ने का अवसर होता है। प्रदेशवासी नव वर्ष का स्वागत, समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भागीदारी, दायित्व बोध के संकल्प के साथ करें। राज्यपाल ने अपने सन्देश में कहा है कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिए नागरिक संकल्पित हों। नागरिकों से अपील की है कि अपने आचरण और व्यवहार से संविधान से प्राप्त अधिकारों और सौंपे गए कर्तव्यों के पालन के लिए प्रतिबद्ध रहकर समरस समाज निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें।

मुख्यमंत्री ने मजदूरों की मृत्यु पर दुःख व्यक्त किया

भोपाल(काप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन जिले के ग्राम डेलची-बुजुर्ग के समीप मजदूरों को रतलाम ले जा रहे पिक अप वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई तीन मजदूरों की असामयिक मृत्यु पर दुःख व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ हैं। डॉ. यादव ने जिला प्रशासन उज्जैन को मृतकों के परिजन को नियमानुसार आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना में घायलों का इलाज महिदपुर अस्पताल में चल रहा है। गंभीर घायलों को उज्जैन जिला अस्पताल में रेफर किया गया। मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिजन को इस गहन दुःख सहन करने की शक्ति देने और घायलों को पूर्णत: शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की प्रार्थना की है।

स्पेडेक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग के लिए दी बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने एक और इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी-सी60 के माध्यम से स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने पर इसरो की समस्त टीम और राष्ट्रवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं।

शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण

200 दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले पात्र

भोपाल(काप्र)।

मप्र में शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को अब 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए वहीं अतिथि शिक्षक पात्र होंगे, जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाया हो। इसका लाभ अतिथि शिक्षकों को हाल ही में होने वाली शिक्षकों की भर्ती में मिलेगा। राज्य कर्मचारी चयन मंडल ने 10 हजार शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम घोषित किया है। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) 2018 में संशोधन कर दिया है। इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

प्रदेश में 72 हजार अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। जिन्हें अब तक शिक्षकों की भर्ती में स्कोर कार्ड के हिसाब से 5 से 20 अंक का लाभ दिया जाता था। सरकार ने पहली बार अतिथि शिक्षकों को शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का लाभ दिया है, लेकिन आरक्षित पदों की पूर्ति अतिथि शिक्षकों से न होने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

महिलाओं को हर श्रेणी में 50 प्रतिशत आरक्षण: महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। जबकि 6 प्रतिशत पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किए गए हैं। प्रदेश में शिक्षकों के अभी 80 हजार पद खाली हैं।

स्पेशल खबर *खाद्य मंत्री की युवा अन्नदूत योजना के हितग्राहियों को नए वर्ष की सौगात...*

3064 रुपए में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के हितग्राहियों को 14 लाख का बीमा

भोपाल(काप्र)।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि युवा अन्नदूत योजना के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं को मात्र 3064 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 14 लाख रुपये का बीमा करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के हितग्राहियों की असामयिक मृत्यु पर कोई सहायता नहीं प्राप्त होने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था।

श्री राजपूत ने बताया कि हितग्राहियों के बीमा के लिये 3 बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा। इनमें से सामूहिक बीमा योजना का क्रियान्वयन फरवरी-2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 2608 रुपये और बीमित राशि 10 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्रियान्वयन जून-2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये और बीमित राशि 2 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्रियान्वयन जून-2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये और बीमित राशि 2 लाख रुपये है।

योजना में पॉलिसी जारी होने की दिनांक से हितग्राही की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पूरी बीमा राशि मिलेगी। पॉलिसी जारी होने की दिनांक से 30 दिन के बाद हितग्राही की अन्य कारण से (दुर्घटना को छोड़कर) मृत्यु होने पर पूरी बीमा राशि दी जायेगी। अन्य कारणों से 30 दिन में मृत्यु होने पर हितग्राही द्वारा देय प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। बीमा पॉलिसी जारी होने के एक वर्ष की अवधि में आत्महत्या करने पर जीवन बीमा की राशि देय नहीं होगी, मात्र देय प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। हितग्राही की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिये। जीवन बीमा एक वर्ष के लिये होगा, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना होगा। हितग्राही की मृत्यु पर बीमा राशि परिवार को दी जायेगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना होने पर दोनों हाथ या दोनों पैर या एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल न होने पाने और एक आँख की रोशनी पूरी तरह से जाने की स्थिति में या दोनों आँखों के ठीक नहीं हो पाने की स्थिति में 2 लाख रुपये का बीमा लाभ मिलेगा। इसी तरह एक हाथ या पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाने की स्थिति में या एक आँख की दृष्टि खो जाने और वापस आ सकने की स्थिति में एक लाख रुपये की बीमा राशि मिलेगी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को उच्च पद का प्रभार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत की पहल पर विभाग में कार्यरत अधिकारियों को उच्च पद का प्रभार देकर इन्हें नव वर्ष की सौगात दी गई है। विभाग के सहायक आपूर्ति अधिकारी के रिक्त पदों पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को उच्चतर पदनाम के साथ पदस्थ किये जाने का निर्णय लिया गया है। शासन मापदण्डों के अंतर्गत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के 65 कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को वर्तमान पदस्थापना वाले जिले में ही उच्च पद का प्रभार दिया जाकर सहायक आपूर्ति अधिकारी का प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह 9 नापतौल निरीक्षकों को प्रभारी सहायक नियंत्रक नापतौल, एक सहायक नियंत्रक नापतौल को प्रभारी उप नियंत्रक नापतौल, एक उप नियंत्रक नापतौल को प्रभारी संयुक्त नियंत्रक नापतौल, 9 सहासक आपूर्ति अधिकारी प्रभारी को प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी और 8 जिला आपूर्ति अधिकारी को प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक बनाया गया है।